भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2221

सोमवार, 09 दिसम्बर, 2024 / 18 अग्रहायण, 1946 (शक)

खाद्य प्रतिष्ठानों को परेशान करना

2221. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना बना रही है कि संचालकों की व्यक्तिगत जानकारी के सार्वजनिक प्रदर्शन का उपयोग खाद्य प्रतिष्ठान मालिकों को परेशान करने के लिए न किया जाए;

(ख) खाद्य उद्योग में शामिल व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों पर इन विनियमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ किए गए विशिष्ट परामर्शों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार इस प्रकार प्रदर्शित की गई जानकारी का तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने को कैसे रोकेगी,

(घ) सरकार कर्मचारियों, जैसे कि शेफ और वेटरों की पहचान से उनकी सुरक्षा से समझौता न हो या वे ग्राहकों या जनता द्वारा अनुचित जांच के दायरे में न आएं यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) अपने संचालकों और कर्मचारियों की गोपनीयता की रक्षा करने में विफल रहने वाले प्रतिष्ठानों पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा और सरकार किस तरह इन विनियमों के अनुपालन की निगरानी करती है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): खाद्य प्रतिष्ठानों सहित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संबंधित राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, जिनके अपने अधिनियम और विनियम होते हैं। इस संबंध में, राज्य सरकारें और संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन समुचित प्राधिकारी हैं।

****